जब संसद भवन में बिना दुआ-सलाम आगे बढ़ गए अमित शाह-राहुल गांधी

नई दिल्ली ,12 मार्च (ए)। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच तनातनी का दौर जारी है और सोमवार को यह संसद भवन में भी देखने को मिला। दोनों नेता पास से गुजरे लेकिन कोई दुआ-सलाम तक नहीं हुआ। दरअसल, हुआ यूं कि देश की दो बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद परिसर में अपॉजिट दिशा से आ रहे थे, पास से गुजरे और बिना नजरें मिलाए आगे बढ़ गए। लेकिन वहां मौजूद मीडियाकर्मियों के कैमरे ने इस दृश्य को कैद कर लिया। विडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों नेता एक-दूसरे को इग्नोर करते हुए गुजर गए। विडियो में राहुल संसद भवन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं जबकि बीजेपी चीफ संसद के अंदर जाते दिख रहे हैं। हालांकि शाह के गुजर जाने के बाद मीडियाकर्मी राहुल की तरफ कुछ बात करने के लिए गए, लेकिन वह भी बिना कोई बात किए वहां से निकल गए। गौरतलब है कि राहुल और शाह के बीच अरसे से जुबानी जंग जारी है। दोनों नेता समय-समय पर एक-दूसरे पार्टी की नीतियों के खिलाफ हमला बोलते रहते हैं। इस घटना को भी इसी तल्खी से जोड़कर देखा जा रहा है।

आज 50 हज़ार रेलकर्मी करेंगे संसद का घेराव

नईदिल्ली ,12 मार्च (ए)। नई पेंशन नीति, न्यूनतम मजदूरी और रेलवे के निजीकरण के खिलाफ रेलकर्मी मंगलवार को संसद का घेराव करने जा रहे हैं. रेल यूनियन का दावा है कि इसमें देशभर से करीब 50 हज़ार रेलकर्मी शामिल होंगे. रेलकर्मियों का आरोप है कि 2004 में पिछली एनडीए सरकार ने नई पेंशन नीति लागू की और उसके बाद से एक ही संस्थान में एक ही पद पर नौकरी कर रहे लोगों के साथ भेदभाव हो गया. ऑल इंडिया रेल मेन्स फेडरेशन का कहना है कि जनवरी 2004 के बाद से 5 लाख लोगों ने रेलवे में नौकरी जॉइन की है और उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलेगी जबकि भारत सरकार की नौकरी में ऐसे कुल 11 लाख लोग हैं. इसके अलावा रेल कर्मी न्यूनतम वेतन को लागू करने और रेलवे को धीरे धीरे निजीकरण की ओर ले जाने का भी विरोध कर रहे हैं. कर्मचारियों का कहना है कि उनका मकसद फिलहाल रेल सेवा को प्रभावित करने का नहीं है लेकिन सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो रेल का चक्का जाम भी किया जाएगा.

देश में रोडरेज की घटनाओं में प्रतिदिन औसतन 3 लोगों की मौत

नई दिल्ली 12 मार्च (ए)। राह चलते छोटी-छोटी बातों पर मारपीट एवं संघर्ष से जुड़ी 'रोडरेज' की घटनाओं के कारण देश में हर रोज औसतन 3 लोग मारे जा रहे हैं और इस गंभीर स्थिति को देखते हुए रोडरेज की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए ठोस कानून बनाने की मांग हो रही है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 में पूरे देश में रोडरेज के 3782 मामले दर्ज किए गए और इन घटनाओं में 4702 लोग घायल हुए तथा इस दौरान मारपीट और संघर्ष में 1388 लोगों की मौतें हुईं। इसी प्रकार से साल 2016 में देश में रोडरेज के 1643 मामले दर्ज किए गए जिनमें 1863 लोग घायल हुए और 788 लोगों की मौत हुई। भाजपा सांसद रत्न लाल कटारिया ने रोडरेज के विषय को लोकसभा में उठाया। कटारिया ने कहा कि उन्होंने संसद में सवाल उठाया और इस विषय की गंभीरता की ओर ध्यान आकृष्ट करवाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यह गंभीर विषय है और देश में रोडरेज की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए ठोस कानून बनाने के बारे में विचार किए जाने की जरूरत है।

महाराष्ट्र की राशन दुकानों में मिलेगा महानंद का दूध

मुंबई12 मार्च (ए)। प्रदेश की सभी सरकारी राशन दुकानों में महानंद का दूध व दुग्धजन्य पदार्थ मिलेंगे। राज्य सरकार ने राशन दुकानदारों को उनके दुकानों में महानंद के उत्पाद बेचने की अनुमति दी है। सरकार के खाद्य, आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण विभाग ने इससे संबंधित शासनादेश जारी किया है। सरकार ने राशन दुकानों की आय में इजाफा करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है। महाराष्ट्र राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ (महानंद) की डेरियों के अधिकृत आपूर्तिकर्ता दूध व दुग्धजन्य पदार्थों को बेचने के लिए सभी राशन दुकानों को उपलब्ध कराएंगे। महानंद की डेरी योजना के अनुसार दूध व दुग्धजन्य पदार्थों के बेचने से मिलने वाले कमिशन के लिए संबंधित दुकानों को महानंद के आपूर्तिकर्ता से संपर्क करना पड़ेगा। यह व्यवहार महानंद डेरी और संबंधित दुकानदारों के बीच होगा। राज्य सरकार इसमें कोई सहयोग अथवा हस्तक्षेप नहीं करेगी।

सिख सैनिक के सम्मान को लंदन में बनाया जाएगा यादगार

मोगा/लंदन, 12 मार्च (ए)। दो विश्व युद्धों की तरफ से ब्रिटेन में लड़ने वाले सिख सैनिक के सम्मान को लंदन में यादगार बनाया जाएगा। जानकारी के अनुसार दो युद्धों में ब्रिटिश आर्मी में 20 फीसदी सैनिक थे। उस वक्त 80 हजार दस्तारधारी सिख शहीद हुए थे तथा एक लाख के करीब सैनिक घायल हुए थे। लंदन में स्मारक बनाने की विभिन्न संगठन करीब एक दशक से मांग कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि ग्रेटर एसैंबली में इकलौते सिख विधायक डॉ. ओंकार सिंह सहोता ने यादगार का प्रस्ताव पेश किया था जिसे प्रस्ताव लूनी कपूर ने आगे बढ़ाया था। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया था। जब लंदन के मेयर भारतीय दौरे पर आए थे तब उन्होंने भी यह मांग की थी। डॉ. सहोता ने प्रस्ताव में कहा था कि मेयर अपनी टर्म पूरी होने से पहले नैशनल सिख फॉर मैमोरियल ट्रस्ट के साथ मिलकर लंदन में स्थायी तौर पर यादगार स्थापित करने के लिए जगह कि तलाश की जाए।

पगड़ी पहनने की वजह से नाइटक्लब से बाहर निकाला गया सिख छात्र

लंदन, 12 मार्च (ए)। ब्रिटेन के एक सिख छात्र के मुताबिक पगड़ी पहनने की वजह से उसे एक बार से बाहर निकाला गया जिसकी वजह से वह पीड़ित महसूस कर रहा है। जानकारी के अनुसार22 साल के अमरीक सिंह ने दावा किया कि उसे पगड़ी पहनने की वजह से कल नाटिंघमशायर के मैन्सफील्ड में रश लेट बार से बाहर जाने को कह दिया गया। सिंह को बताया गया कि बार में' सिर पर कुछ नहीं पहनने की' नीति लागू है। सिंह के अनुसार उसने बाउंसर को बताया कि पगड़ी से उसके केशों की रक्षा होती है और यह उसके धर्म का हिस्सा है लेकिन उसकी यह बात नहीं सुनी गयी और पहले उसके दोस्तों के पास से खींचकर अलग किया गया और बाद में बार से बाहर निकाल दिया गया।

अवैध माइनिंग की जांच रिपोर्ट विधानसभा सेशन को सौंपेंगे सिद्धू

जालंधर 12 मार्च (ए)। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवोजत सिंह सिद्धू ने कहा कि अवैध माइनिंग के कारोबार में शामिल नेताओं, अधिकारियों के नैक्सस के वह कचे चिट्ठे खोलेंगे। पंजाब में अवैध माइनिंग पर कैबिनेट सब-कमेटी विधानसभा सैशन के 1 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप देगी। इस जांच में जो भी राजनीतिज्ञ व अधिकारी शामिल हुआ उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि खड्डों से रेत निकालने में पोक-लेन मशीनें कानूनी तौर पर लगाई नहीं जा सकतीं। माइनिंग में ये मशीनें कैसे व किसने लगाईं यह जांच का विषय है। सिद्धू ने बताया कि माइनिंग के टैंडर छोड़कर भागे ठेकेदारों से मीटिंग कर उनसे टैंडर छोड़ने का कारण पूछा जाएगा। इसके साथ ही अवैध वसूली में शामिल लोग भी बेनकाब होंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर व हिमाचल से रेत बजरी के 2600 ट्रक पंजाब आते हैं और इन ट्रकों से 5000 रुपए की नाजायज वसूली होती थी। पंजाब सरकार खुद एंट्री टैक्स लगाकर टैक्स वसूले तो करोड़ों रुपयों का राजस्व हासिल होगा।

10 साल राज करने वाले सुखबीर अब 2 महीनों की मांग रहे हैं भीख : पंजाब में 10 सालों तक राज करने वाले सुखबीर बादल आज किस मुंह से 2 महीनों की भीख मांग रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने सुखबीर पर राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि 10 सालों तक प्रदेश की जनता के साथ लूट-खसूट मचाने और प्रदेश का खजाना खाली करने वाले अब बड़े-बड़े झूठ बोलने लगे हैं कि उन्हें 2 महीनों के लिए पंजाब की बागडोर देकर देखो वह खजाने को भरके दिखा देंगे। सिद्धू ने बताया कि कै. अमरेन्द्र सरकार ने 1 साल में वे काम करके दिखा दिए हैं जिन्हें बादल सरकार 10 सालों में नहीं कर सकी। सिद्धू ने कहा कि पंजाब में ई-गवर्नैंस सिस्टम लागू करके भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर लगाम लगाई जाएगी। इस वर्ष के अंत तक 67 सर्विसिस ऑनलाइन होंगी, अगले 3 महीनों में नक्शे ऑनलाइन पास होने शुरू हो जाएंगे। सिद्धू ने कहा कि पंजाब के 4 बड़े नगर निगमों व 4 इम्प्रूवमैंट ट्रस्टों का 10 सालों के आडिट का काम चल रहा है। अभी अढ़ाई महीने हुए हैं, 6 महीनों के भीतर यह काम पूरा कर लिया जाएगा जिसके उपरांत करोड़ों रुपए के घपले सामने आएंगे। 200 करोड़ की लागत से जीरकपुर में बनेगा विश्व स्तरीय सैंटर ऑफ एक्सीलैंस पंजाब के जीरकपुर में 200 करोड़ रुपयों की लागत से अंगहीन/पैरा स्पोर्ट्स खिलाड़ियों का सैंटर ऑफ एक्सीलैंस बनाया जाएगा। उक्त जानकारी निकाय मंत्री नवजोत सिद्धू ने जालंधर व रूप नगर में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। सिद्धू ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जीरकपुर सहित ग्वालियर व विशाखापट्टनम में देश के 3 ऐसे सैंटर बनाए जा रहे हैं जिसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजैक्ट के लिए पंजाब सरकार ने नगर कौंसिल जीरकपुर को करीब 50 करोड़ रुपयों की बेशकीमती जमीन अलाट करने की फाइल को मंजूरी दे दी है। अब केंद्र सरकार 150 करोड़ रुपयों की लागत से अढ़ाई वर्षों में इस सैंटर को बनाएगी। सिद्धू ने कहा कि उनकी सोच है कि डिस्एबल खिलाड़ियों को सहानुभूति की बजाय सम्मान दिया जाए ताकि उनमें हीन भावना न पैदा होने पाए। उन्होंने बताया कि नया सैंटर जहां भारत के लिए पैरालिम्पिक खिलाड़ी तैयार करेगा, वहीं उन्होंने कहा कि पैरा-स्पोर्ट्स के साथ जुड़े कोचों, तकनीकी स्टाफ व वालंटियरों को तैयार करेगा।

संपत्ति बेचकर ग्राहकों का पैसा चुकाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट का यूनिटेक को झटका

नई दिल्ली ,12 मार्च (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन जायदाद का कारोबार करने वाली कंपनी यूनिटेक लि को आज अपनी देनदारी मुक्त संपत्तियों का विवरण देने का निर्देश दिया और कहा कि इन सम्पत्तियों को नीलाम किया जाएगा ताकि कंपनी के मकानों के ग्राहकों का फंसा पैसा लौटाया जा सके।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई. चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इसके साथ ही जे. एम. फाइनेन्शियल रिकंशट्रक्शन कंपनी पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस कंपनी ने एचडीएफसी बैंक द्वारा यूनिटेक लिमिटेड को दिए गए कर्ज में से कुछ कर्ज को खरीद लिया था। पीठ ने कहा कि रिकंशट्रक्शन कंपनी की संपत्ति ने ऐसा आभास कराया था कि वह मकान खरीदारों को धन लौटाने के लिए पैसा देगी और अब सारी रकम दूसरे काम में लगा दी गई है।

पीठ ने इस पर जुर्माना लगाते हुए कहा कि हम इसे मुख्य मामले से एक अनावश्यक भटकाव के रूप मे देखते हैं।''

पीठ ने रियल इस्टेट कंपनी को अपनी समस्त देनदारी मुक्त संपत्तियों का विवरण देने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि परेशान मकान खरीदारों के सौदों के निबटारे के लिए इसकी नीलामी की जाएगी। कंपनी को संपत्तियों का विवरण आज से 15 दिन के भीतर देना है। इस कंपनी ने पांच मार्च को कोर्ट से कहा था कि मुंबई स्थित जे. एम. फाइनेन्शियल लि की उसकी निर्माणाधीन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने में दिलचस्पी है।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 30 अक्तूबर को कहा था कि यूनिटेक लि के प्रबंध निदेशक संजय चन्द्रा को रजिस्ट्री में अपेक्षित धन जमा करने पर ही जमानत दी जाएगी। संजय चन्द्रा इस समय तिहाड़ जेल में बंद है।

राशन की दुकानों में जून तक अनाज की कीमत नहीं बढ़ेगी : पासवान

नई दिल्ली 12 मार्च (ए)। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने रविवार को कहा कि इस वर्ष जून तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दिए जा रहे गेहूं और चावल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

पासवान ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद संवाददाता समेलन में कहा कि जून तक दो रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और तीन रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल मिलता रहेगा। खाद्य सुरक्षा कानून में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मिलने वाले गेहूं और चावल के मूल्य में हर तीन साल पर समीक्षा की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में जिस कीमत पर गेहूं और चावल दिया जा रहा था उसी कीमत पर अब भी इसे दिया जा रहा है।

पुलिस ने सेना पर मढ़ा लेक्चरर की हत्या का आरोप, केस चलाने के लिए मांगी इजाजत

श्रीनगर, 12 मार्च (ए)। कश्मीर में एक कॉलेज लेक्चरर की मौत के मामले में पुलिस ने अपनी जांच में भारतीय सेना के 23 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। ये लोग 50 राष्ट्रीय राइफल्स (आर.आर.) से ताल्लुक रखते हैं। राज्य पुलिस ने इसी के साथ इन लोगों के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मांगी है। आरोप है कि साल 2016 में लेक्चरर की मौत सेना की हिरासत में बेरहमी से पीटे जाने के कारण हुई थी। अवंतिपुरा एस.एस.पी. मोहम्मद जाहिद ने बताया कि दो हफ्ते पहले इस मामले में विशेष जांच दल (सिट) ने जांच पूरी की थी। अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। हमें उनके (सेना के लोगों) खिलाफ केस चलाने के लिए ऑर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट (एफएसपीए) के तहत मंजूरी चाहिए होगी। ऐसे में मैं अभी जांच के अंतिम निष्कर्ष के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बता दें कि 17 अगस्त 2016 की रात को शब्बीर अहमद मंगो नाम के लेक्चरर की मौत हो गई थी। आरोप है कि दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के शारशाली गांव में सेना के लोगों ने उन्हें पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया था। यह भी दावा किया गया था कि सेना के लोगों ने गांव वालों को लकड़ी के तख्तों, सरिया और राइफल की बट से पीटा था। ग्रामीणों के अनुसार सेना के लोग शब्बीर के घर में घुस आए थे। वे उसे घसीटते हुए बाहर लाए थे और पीटने लगे थे, जिसके बाद वे उसे अपने साथ ले गए थे। शब्बीर के साथ गांव के अन्य 20 नौजवानों को भी सेना के लोग अपने साथ ले गए थे। बाद में उसी रात सैनिक लेक्चरर समेत तीन लोगों को थाने ले गए। शब्बीर की हालत नाजुक थीए लेकिन पुलिस वाले उसे वापस ले जाने के लिए कह रहे थे। उसने पानी मांगा था, जिसके बाद वहीं उसने दम तोड़ दिया। फिर उसकी लाश पंपोर के उप.जिला अस्पताल ले जाई गई। सीएम महबूबा मुफ्ती ने इस मामले पर सेना के आरोपी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे। विधानसभा में सीएम ने ऐलान किया था कि राज्य पुलिस एसआईटी मामले की जांच करेगी।

आरपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज : पुलिस ने इस मामले में रणबीर पेनल कोड (आरबीसी) की धारा 364, 302, 307, 447, 427, 120.बी के तहत पंपोर पुलिस थाने में सेना के 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि, सेना की ओर से बाद में जवाबी एफआईआर दाखिल की गई, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि शब्बीर की मौत में सेना के लोगों का कोई हाथ नहीं है। मगर इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। मेजर, 50 आरआर की ओर से दर्ज कराई गई इस एफआईआर में कही गई।

मुख्यमंत्री योगी को भरोसा: एक फीसदी अधिक मतदान से भाजपा को 10 हजार वोटों का फायदा

गोरखपुर 12 मार्च (ए)। गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में विरोधी मतों के ध्रुवीकरण की चुनौती से परेशान भाजपा की निगाहें गोरखपुर शहर विधानसभा पर टिक गई है। गोरखपुर लोकसभा के पांच विधानसभा सीटों में से गोरखपुर शहर विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां से बीजेपी को हर चुनाव में बड़ी बढ़त मिलती रही है। इस बढ़त को निर्णायक बनाने का प्रयास बीजेपी के रणनीतिकार कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार शाम टाउनहाल की सभा में इस रणनीति का संकेत दिया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से शहर विधानसभा में मत प्रतिशत बढाने का आह्वान किया और कहा कि यदि शहर विधानसभा क्षेत्र में यदि 60 फीसदी मतदान प्रतिशत हुआ तो यहां से बीजेपी को ढाई लाख की लीड मिल जाएगी। इसके पहले पांच मार्च को राप्तीनगर की सभा में भी योगी आदित्यनाथ ने यही बात कही थी।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शहर विधानसभा में मतदान यदि एक प्रतिशत अधिक होने का मतलब है कि बीजेपी को दस हजार वोटों की बढ़त होगी। योगी आदित्यनाथ यह कहना चाहते थे कि यदि शहरी विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत 60 फीसदी गया तो यह बढ़त ढाई लाख की हो जाएगी और दूसरे विधानसभा क्षेत्रों मे यदि विरोधी अधिक मत पा भी जाते हैं तो उनके लिए इस लीड को पाटना असंभव हो जाएगा।

आंकड़ों की कसौटी पर योगी आदित्यनाथ की बातें एकदम सही है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखें तो गोरखपुर शहर विधानसभा सीट ही बीजेपी का अभेद्य किला है। वर्ष 1999 में भी जब योगी 7339 मतों के मामूली अंतर से जीते थे तब शहर विधानसभा की लीड ने ही उन्हें जीत का अवसर प्रदान किया था। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र की सभी पांच सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी। इस लोकसभा क्षेत्र की गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की सीट से भाजपा प्रत्याशी 4410 मत से विजयी हुआ। सहजनवां में 15377, पिपराइच में 12809, कैम्पियरगंज में 32854 मतों से भाजपा प्रत्याशी की विजय हुई। गोरखपुर शहर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी 60370 मतों से जीते। सभी पांच विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक अंतर से यहीं पर भाजपा की जीत हुई। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को सबसे अधिक मत गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से ही मिला था। उन्हें 133892 मत मिले थे और और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी से 1,02,837 मत से बढत बनाई थी। शेष चार विधानसभाओं में से कैम्पियरगंज से उन्हें 42041, पिपराइच से 77479, गोरखपुर ग्रामीण से 43670 तथा सहजनवां से 46354 मतों की बढ़त मिली थी।

वोटर आईडी को आधार से जोड़ना हो अनिवार्य, चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट से गुहार

नई दिल्ली, 12 मार्च (ए)। चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन पत्र दाखिल किया है, जिसमे वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार नंबर को लिंक करना अनिवार्य करने की अपील की गई है । चुनाव आयोग ने अपनी अपील में आधार की वोटिंग कार्ड से बाध्यकारी लिंकिंग के लिए गुहार लगाई हैं । जिसके मुताबिक अगर आने वाले समय में ऐसा होता हैं तो देश में होने वाले चुनावो में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में बड़ी सफलता हाथ लग सकेगी । चुनाव आयोग इसको अनिवार्य इसलिए भी बनाना चाहता है क्योंकि सरकार ने पिछले साल आधार कानून पारित किया था । इस से पहले जब ये मामला अदालत में गया था तब कोर्ट ने इसे स्वैच्छिक बताया था। इससे पहले हो चुकी सुनवाई में आयोग ने कोर्ट में कहा था कि वोटर आईडी की आधार से लिकिंग बाध्यकारी नहीं है, यह वोटर की इच्छा पर निर्भर करता हैं कि वो लिंकिंग करवाए या फिर नहीं । आयोग ने सबसे पहले 2015 में इलेक्टर्स फोटो आईडेंटिटी कार्ड की आधार से लिंकिंग शुरू की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक साल बाद आयोग की इस योजना को बंद कर दिया गया था । कोर्ट ने अपनी टिपण्णी में कहा था कि आधार लिंकिंग केवल एलपीजी और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए होनी चाहिए। वही जुलाई 2017 में इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग कार्ड और आधार लिंकिंग प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, उस वक्त चुनाव आयोग ने लिंकिंग को बाध्यकारी नहीं बल्कि स्वैच्छिक बताया था ।

चीन का डिजिटलीकरण के तरफ नया कदम, 6 जी तकनीक पर शुरू किया काम

बीजिंग, 12 मार्च (ए)। दुनियाभर में इंटरनेट के यूजर्स बढ़ रहे हैं। जिस गति से इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं उसी के साथ-साथ इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। चीन ने अब 6त्र तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया है। चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मोआओ वेई ने मोबाइल संचार नेटवर्क की अगली पीढ़ी 6जी में अनुसंधान की शुरुआत की घोषणा की है। वेई ने कहा कि अनुसंधान की शुरूआत इंटरनेट के लगातार विस्तार और विकास से जुड़ी हुई है। मंत्री ने कहा कि भविष्य में ड्राइवरलैस कारों और जीवन के समग्र डिजिटलीकरण का उपयोग करने के लिए एक तेज नेटवर्क की आवश्यकता होगी, जो उचित कार्य के लिए भारी मात्रा में डेटा स्थानांतरित करने में सक्षम हो। बता दें कि वर्तमान में चीन हार्डवेयर संबंधी समाधानों पर काम कर रही दो प्रमुख चीनी कंपनियां, हूवेई और जेडटीई 5 जी संचार नेटवर्क प्रौद्योगिकी पर काम कर रही हैं।

मुस्लिम विरोधी चिट्ठियों की जांच में जुटी ब्रिटेन की पुलिस

लंदन, एजेंसी। ब्रिटेन के आतंकवाद निरोधक अधिकारी देश के कई हिस्सों में सामने आई उन मुस्लिम विरोधी चिट्ठियों की जांच कर रहे हैं जिनमें लोगों से तीन अप्रैल को'' एक मुस्लिम को सजा दो दिवस'' के तौर पर मनाने और इसमें हिस्सा लेने की अपील की गई है। इंग्लैंड में लंदन, यॉर्कशायर और मिडलैंड्स क्षेत्र के निवासियों ने ऐसी चिट्ठियां मिलने की सूचना दी है। पुलिस ने इन चिट्ठियों को'' दुर्भावनापूर्ण पत्र'' करार दिया है। वेस्ट यॉर्कशायर की पुलिस ने कहा कि ब्रिटेन की नॉर्थ ईस्ट काउंटर टेररिज्म यूनिट(एनईसीटीयू) घटना की जांच कर रही है और मामले की पूरी छानबीन जारी है। सहायक मुख्य कॉन्स्टेबल एंजेला विलियम्स ने कहा, ''मैं वेस्ट यॉर्कशायर के लोगों को आश्वस्त करना चाहती हूं कि इन चिट्ठियों को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। हम समझते हैं कि इससे चिंता पैदा हो गई होगी और लोग, खासकर समाज के कमजोर वर्ग, निराश हुए होंगे।'' उन्होंने कहा, ''लोक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और मैं लोगों से अपील करूंगी कि वे चौकस रहें, लेकिन डरें नहीं।